

Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Government of Manipur for the year 1973-74

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindis showing the Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Government of Manipur for the year 1973-74.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Seizure of D.M.S. Bottle caps from a milk depot in Delhi and decision of D.M.S. to Supply Toned Milk only.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत (राजस्थान) : श्रीमान्, दिल्ली में दूध के एक डिपो पर अचानक मारे गये एक छापे के बाद दिल्ली दुग्ध योजना की बोतलों के ढक्कनों के पकड़े जाने और उपभोक्ताओं को केवल टोन्ड दूध सप्लाई करने के दिल्ली दुग्ध योजना के निर्णय की ओर मैं कृषि मंत्री का ध्यान दिलाती हूँ।

THE MINISTER OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): Sir, the officers of the Delhi Milk Scheme regularly inspect the functioning of the milk depots in the city. From time to time special surprise inspections are also carried out, both *suo-moto* and on receipt of specific complaints. In the Course of such inspections all aspects of the functioning of depots and the conduct of the depot agents are examined. In cases in which the adoption of any malpractices come to notice, immediate action is taken to stop such mal-practices as also against the defaulting depot agents. On 21st of August, 1973, a special check was carried out in respect of Depot No. 065 in Gopinath Bazar, Delhi Cantonment by the field officers of the D.M.S. and it was observed that the depot agents with the

assistance of a private individual, were affixing standardised milk aluminium foil caps on some milk bottles the caps of which had been removed. Some toned milk bottle were also recovered from the private individual who had unauthorisedly entered the depot. The entire staff of this depot have been taken off duty and alternative arrangements have been made for distribution of milk from this depot. Since no specific instance has been mentioned in the Notice by the Hon'ble Member and in view of the fact that the aforesaid incident was reported in a section of the Press, presumably the Member is referring to this incident.

Regarding the decision of the D.M.S. to supply toned milk in place of standardised milk for about a week with effect from 23rd August, 1973, it may be stated that due to adverse weather conditions on the seas during the present monsoon season as well as the delay in providing berthing facilities to the ships carrying butter oil due to the congestion at Bombay port, the current shipments of butter oil have been unduly delayed. Butter oil is used for the re constitution of milk, specially- during the summer and rainy seasons which are lean seasons for milk production, to supplement the fresh milk intake in order to cater to the distribution requirements. Due to the delay in the arrival of the shipments of butter oil the position regarding the availability of fat required for the processed milk has temporarily become difficult and in order to tide over this temporary phase it became unavoidable to issue toned milk which contains less fat, in place of standardised milk to the consumers for a few days. It may, however, be clarified that the total quantity of milk distributed will remain unchanged except for occasional marginal reductions even during this period. Arrangements have been made to procure additional lilies of white butter to the extent presently available as well as to ensure the expeditious despatch and transportation of butter oil to the D.M.S. and it is hoped that it would be possible to restore at 50% of the standardised milk supplies within a week. It may be added that the Delhi Milk Scheme has all along been ensuring full supplies of milk to its consumers even during the recent summer

[Prof. Sher Singh) season with the exception of a few days interruption due to a major break-down in the power supply to its Central Dairy. It is due to the difficult position resulting from the deficiency in the supply of butter oil that 50% of the standardised milk supply had to be converted into toned milk in August 9, 1973 and now with effect from 23rd August for a few days only toned milk is being issued in place of standardised milk. It is planned to restore atleast 50% of the standardised milk supply within a week and the balance progressively thereafter. However, the total quantum of milk distribution has hitherto been maintained at normal levels by utilising 100% of the installed plant capacity and all efforts are being made to continue to do so. All the aforesaid changes that were made in the pattern of milk distribution during this month have been widely notified in the Press as well as through Notices affixed on the milk booths for the information of the consumers. [Mr. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : उप-सभापति जी, मैंने जान-बूझकर यह प्रश्न हिन्दी में पढ़ा। मुझे उम्मीद थी कि मंत्री जी हिन्दी में उत्तर देंगे। आपसे उम्मीद थी कि आप भी हिन्दी बोलने वाले हैं और मैं भी हिन्दी में बोलती हूँ, इसलिए आप हिन्दी में बोलेंगे।

आपने जो दूध के बूथों पर छापे मारे, कुछ बोतलों को पकड़ा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ या कांग्रेसचुलेशंस देती हूँ।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : बहन जी, मिनिस्टर साहब ने नहीं पकड़ा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : इनके विभाग ने पकड़ा। लेकिन आपने जो जवाब दिया और इस बात को इतना महत्व और आसानी में लिया, मैं समझती हूँ कि यह प्रश्न इतना आसानी से आपको नहीं लेना चाहिए था। जिस तरह से मिलावट हो रही

है, जिस तरह से चारों तरफ से हमें मिलावटी चीजें मिल रही हैं, यह आज हमारे सामने अहम् प्रश्न है। दूसरी दुकानों पर जहाँ प्राइवेट व्यापारी मिलावट करते हैं, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जहाँ सरकारी व्यवस्था में दूध दिया जाए और उसमें भी मिलावट होने लग जाए तो यह बहुत ही बड़ी गम्भीर समस्या हमारे सामने है। आपने जो बोतलों के कैप्स पकड़े, उसके दोनों कारण हो सकते हैं। एक तो स्टैंडर्ड मिल्क के कैप लगा कर टोन्ड मिल्क दिया जाता है। दूसरे उन दूध की बोतलों में पानी या दूसरे तरह की मिलावट होती है। इस तरह का दूध सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत दिया जाना एक चिन्तनीय चीज है। उस हालत में हमारा स्वास्थ्य क्या हो रहा है? आपने जो टोन्ड दूध देना शुरू किया है, इसी तरह बच्चों को और कोई चीजें खाने पीने की नहीं मिलती अगर उन्हें स्टैंडर्ड दूध भी नहीं मिल पाया तो हमारे बच्चों का क्या स्वास्थ्य बनेगा? क्या वह नॉर्मेब? आप हरियाणा जिले से आने वाले हैं, जहाँ कहते हैं कि दूध की नदियाँ बहती हैं, लेकिन दिल्ली में बच्चे पीने के दूध के लिए भी तरस रहे हैं।

दूसरे, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जो आपके यहाँ कार्ड बनते हैं, उनका एक रैकेट चल रहा है। फर्जी कार्ड बनाये जाते हैं। दूध की एक-एक बोतल के दस-दस पैसे लेकर दूसरे लोगों को यह दूध पहुंचाया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत चिन्ता की बात है।

यह शायद मेरी जानकारी में नहीं था, आपने बताया कि बटर आयल के शिप नहीं आने की वजह से आप स्टैंडर्ड दूध नहीं दे सकते हैं। इसका

मतलब यह हुआ कि हमें दूध पीने के लिए भी विदेशों का मुहं ताकना पड़ता है। जहां की 80 प्रतिशत जनता किसान मानी जाती है, जहां करोड़ों की संख्या में कैटल हैं, वहां के मुल्क वाले विदेशों से जब जहाज आये तब उनको दूध मिले, इससे बढ़ कर हमारे लिए लज्जाजनक चीज नहीं हो सकता है। पीने के दूध के लिए भी हमको बाहर के देशों का मुहं ताकना पड़ता है।

मंत्री जी, आज हर एक चीज मिलावट की मिलती है। कोका कोला की बोतलों में दूसरी चीजें मिला कर नकली चीजें दी जा रही हैं। आज स्थिति यह है कि कोई शुद्ध वस्तु हमें खाने के लिए नहीं मिल सकती। धनिया जो पिसा हुआ होता है उसमें घोड़े की लीद मिलाई जाती है। (*Interruptions*) कलकत्ता में गोबर के गोदाम पकड़े गये हैं जो चाय में मिलाया जाता था

(*Interruptions*)

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Don't (five him new ideas.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत : उन्हें इससे ज्यादा आडिया का पता है। मैं एक मिनट में समाप्त करती हूं। आज हालत यह है कि खाने के लिए शुद्ध अहर तक नहीं मिल सकता है।

प्रो० शेर सिंह : उपसभापति महोदय, मैंने जो वक्तव्य दिया...

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : उसमें कोई मिलावट नहीं है।

प्रो० शेर सिंह : ... उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने चिन्ता प्रकट न की हो। यह चिन्ता का विषय है कि दूध जैसा मिलना चाहिए वह लोगों को मिलता नहीं है और उसमें हेराफेरी होती है। इसलिए हम यत्न

करते हैं कि जब भी कोई ऐसी शिकायत आये तो उसकी जांच करवाई जाय ताकि ऐसी गड़बड़ न हो। यह केस तो अभी पकड़ा गया जो नोटिस में आया। पिछले तीन महीनों में हमारे पास करीब 468 शिकायतें आईं। उनमें से 38 प्रतिशत के करीब शिकायतों की जांच की तो वे ठीक मिलीं और 62 प्रतिशत के करीब जो थीं वे साबित नहीं हो सकीं या ठीक नहीं मिलीं, गलत थीं। उसमें से हमने 28 व्यक्तियों को जो एजेंट के तौर पर काम करते हैं, वहां पर डिपोज के अन्दर उनको निकाला, सर्विस से हटाया। आम तौर पर जो युनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं जो इस काम पर लगे हुये हैं उनको कुछ सहायता मिल जाती है। उनको करीब 30 रु० मासिक, 50 रु०, 60 रु० के बीच मासिक मिल जाता है। उनमें से जो सीनियर एजेंट होता है उसको 1 रु० 87 पै० मिल जाते हैं और जूनियर एजेंट को 87 पै० रोज मिल जाते हैं। वे एक घंटे काम करते हैं। उनमें से जब किसी के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत मिलती है और वह साबित हो जाती है तो उसको हटा भी देते हैं, बदल भी देते हैं। एक आध सुपरवाइजर करने वाले जो आफिसर हैं उनके बारे में शिकायत आई तो उनकी भी जांच कर के उनको हमने चार्जशीट किया। जब भी हमें कोई पता लगता है तो उसकी हम तुरन्त जांच करवाते हैं। यह बक्कन बदलने की बीमारी बहुत बढ़ रही है; क्योंकि टोन्ड मिल्क और स्टेन्डर्ड-इज्ड मिल्क के मूल्य में बड़ा अन्तर है, 32 पै० का अन्तर है। वैसे इंड परसेंट फैट का भी फर्क है। यह अन्तर होने की वजह से यह गड़बड़ होता है। इसके लिए हम यह सोच रहे हैं कि सवेरे केवल स्टैंडर्डइज्ड

[प्रो शेर सिंह]

मिल्क दिया करें। इसके बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं कि इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आयेगी, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि कुछ लोग एक ही समय पर दूध लेते हैं। इसके लिए हम यह सोच रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था बन सके जिससे एक समय केवल टोन्ड मिल्क और एक समय केवल स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क मिल सके से अदला-बदली की बात न हो सके और आसानी से काम चल सके।

दूसरी बात जो माननीय सदस्या ने मिलावट की कही, तो इसमें मिलावट की ज्यादा बातें नहीं आती हैं, बातें ज्यादा इक्कन बदलने की आती हैं। मिलावट की एक आय बातें आती हैं तो उसकी भी हम जांच करते हैं और उसमें जो कसूरवार हो उसको सजा मिलती है।

बटर आयल के बारे में जो बात कही कि हमने यह स्पष्टीकरण दिया कि बटर आयल ठीक समय पर न पहुंचने की वजह से हम को कठिनाई हो रही है, तो इसका कारण यह है कि इन दिनों दूध कम मिलता है और तीन लाख लीटर के करीब सप्लाय करनी पड़ती है। अभी शायद 40, 42 या 45 हजार लीटर दूध आया; क्योंकि जन्माष्टमी की वजह से दो तीन दिनों में कमी हो गई थी, लेकिन अब वह फिर बढ़ेगा। फिर भी हमें कमी भी दो लाख लीटर से ज्यादा दूध नहीं मिलता है। फिर रिकम्बाइन्ड मिल्क जो है वह हमें देना पड़ता है। जो विदेशों से बटर आयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर आता है, उसकी सहायता से दूध बना कर हमें देना पड़ता है। लीन मन्थ्स में बटर आयल की कमी पड़ जाय तो ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि फ्रेश

मिल्क कम मिलता है। हम यह चाहते हैं कि जितना दूध हम दे रहे हैं उतना हम देते रहें। हमने यह भी सोचा कि कहीं दूध की सप्लाय बिलकुल बन्द न हो जाय इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क से डेढ़ परसेंट फैट कम कर वह दूध पुरे का पूरा टोन्ड मिल्क के रूप में दे दिया जाय। यह हमने यत्न किया कि बटर आयल का शिपमेंट आने के बाद उसको उतार कर के जल्दी हम ले आयें और उसी समय हम इसको रेस्टोर कर देंगे। हमें 60 टन के करीब इत महीने में कमी पड़ी थी। उसी के कारण पहले से सोच कर के हमने ऐसा किया इसमें कुछ सुधार हो सकता है, अगर हमें कुछ व्हाइट बटर मिल जाय। जो मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्रीज हैं, उनसे हमने कोशिश की है और 35 टन के करीब हमसे वादे हुए हैं। लेकिन उम्मीद ऐसी है कि शायद 25 टन मिल सके। तो उस कमी को जितना भी पूरा कर सकते हैं वह पूरा करने का यत्न कर रहे हैं और जैसे ही बाहर से बटर आयल आयोग वैसे ही पूरी सप्लाय स्टैंडर्ड मिल्क की धीरे-धीरे पूरी कर देंगे।

श्री नवल किशोर : श्रीमन्, मुझे इस बात का ताज्जुब है कि प्रोफेसर शेर सिंह साहब हरियाणा से आते हैं, तो खुद वह अपनी गाय भैंस अपनी कोठी पर रखते हैं या यहीं दूध पीते हैं।

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) : आपको भी दूध की जरूरत है।

श्री नवल किशोर : सुनिये। मैं चाहता हूं कि आप दूध पियें। रणवीर सिंह जी हैं, आप हैं, कपूर साहब हैं, इनकी तो कोई बात नहीं लेकिन अगर लोकनाथ मिश्र जी को टोंड मिल्क है तो यह और भी ज्यादा दुबले हो जायेंगे।

मेरी भी कोई बात नहीं। काम चल जायगा। और जैसा कि बहन चूड़ावत जी ने कहा कि शुद्ध जहर भी खाने को नहीं मिलता है, जहर भी खाना चाहें तो वह भी नहीं है हां, उससे फायदा यह है कि स्युसाइड नहीं होगा, वह शुद्ध नहीं है तो मरेंगे नहीं। यह ठीक बात कही।

श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) : नवल किशोर जी, कभी जहर खा कर देखे तो। आपको क्या जरूरत पड़ी।

श्री नवल किशोर : मुझे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी तरफ के लोगों को उसके खाने की नौबत पड़ने वाली है। अच्छा है, जहर खा कर मरेंगे नहीं।

श्रीमन्, तो आपने रेड किया और उसमें आपने पकड़ा। तो असली कारण यह नहीं था कि वहां बोतल की अदला-बदली होती है, यह पता चला कि चूक बटर आयल नहीं मिल रहा है, इसलिये टॉड मिलक की बात की गई है यह कारण है इसलिए यह टॉड मिलक की बात है। मगर वह एक हफ्ते में समाप्त हो जायगा, इसलिए अभी फिलहाल कंज्युमर्स को टॉड मिलक दे रहे हैं तो इन कंज्युमर्स में मिनिस्टर्स और हाई आफिशियल्स भी इंकलूडेड हैं या नहीं इंकलूडेड हैं। आपने सिर हिला दिया लेकिन मैं जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। श्रीमन्, यहां पर मक्खन की स्थिति यह है कि मक्खन किसी इंसान को नसीब नहीं हो रहा है, यह दूसरी बात है कि आपके यहां मक्खन पहुंच जाता है। घी की हालत यह है कि वह मिनिस्टर्स को, आफिसरान को, सेक्रेटरीज को मिल जाता हो, तो मिल जाता हो, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के डिपो में वह आउट आफ स्टॉक है।

डा० भाई महावीर : 7 जुलाई से नहीं आया।

श्री नवल किशोर : मैं कोई स्पेशल फ़ेवर नहीं चाहता, मगर मिनिस्टर्स को कम से कम अपने आपको मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट की कैटेगरी में रखना चाहिये। आपको तमाम दुनिया की चीज मुहैया हो जाय, आपके पास गाय और भैंस भी हो और हमको तमाम तरह की मिलावट का दूध दें। आप इस बात को सोचिये।

डा० भाई महावीर यहां हैं। यह डाक्टर नहीं है, मेडिकल डाक्टर नहीं हैं। डा० भाई महावीर ने यहां शीशी पेश की दूध की। आज श्याम लाल जी गुप्ता भी एक शीशी ले कर आये हैं।

श्री श्याम लाल गुप्त (बिहार) : मैं ले कर आया हूं। मैं पेश करूंगा।

श्री नवल किशोर : वह उन्होंने यहां खरीदी है, जो पार्लियामेंट हाउस में मिल्क बूथ है उसने सप्लाय की है।

श्री रणवीर सिंह : श्याम लाल जी, आपने उसमें क्या भर कर रखा है।

श्री नवल किशोर : चौधरी साहब, अगर आपने यह तय कर लिया है कि सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू आपकी हाउस में है तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन कभी तो सेंस की बात किया करें। *Time bell rings* श्रीमन्, मैं खत्म करता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने चूहा दिखाया और यह पता नहीं कि यह क्या-क्या चीजें दिखाने वाले हैं। बहन जी ने कहा कि घनिया में घोड़े की लीद होती है, गोबर होता है और बेजेटेबिल घी से भी गोबर निकल रहा है। तो आखिर इस सबका कुछ होना चाहिए। हाउस में इतना शोर मचता है, इतना ध्यान दिलाया जाता है। आज नन्दा जी, वह ग्रेट नन्दा जी अब एडलटेशन

[श्री नवल किशोर]

कमेटी के कोई चेयरमैन बगैरह हो गये हैं या क्या हो गये हैं मुझे पता नहीं।

श्री कृष्ण कान्त (हरियाणा) : एडलट्रेशन नहीं, एंटी एडलट्रेशन कमेटी के।

श्री नवल किशोर : ठीक है, एंटी एडलट्रेशन के। श्रीमन्, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह इतनी हंसी मजाक की बात नहीं है, इसमें शर्म आनी चाहिये, हम सब को शर्म आनी चाहिये, लेकिन आपको ज्यादा शर्म जानी चाहिये। दूध की ही बात नहीं, हर चीज में तीन महीने में क्या जादू हो गया क्या समाजवाद आ गया कि खाने की चीज, पीने की चीज, दूध, मक्खन, हर चीज गायब हो गई। माननीय मंत्री जी को इस पर कुछ कहना हो तो फर्मायें और यह भी बता दें कि आपके यहां गाय भैंस हैं या नहीं। अपनी तो भैंस का दूध पीते हैं बैठ कर हमको देते हैं टोन्ड मिल्क।

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य ने प्रश्न तो ज्यादा नहीं किये, लेकिन एक-आध बातें कहीं। एक तो आपने कहा कि सिर्फ मिनिस्टर्स को घी मिल जाता है बाकी को नहीं मिलता है—उनका मतलब दिल्ली मिल्क स्कीम के घी से है (Interruptions) हां, न तो मिनिस्टर्स को, न सेक्रेटरी को, किसी को भी 7 जुलाई के बाद घी नहीं मिला है; क्योंकि मार्च के महीने के बाद घी नहीं बन सका। जो मार्च के महीने में घी बना उसके बारे में यह था कि 4 महीने बाद उसको रखें तो खराब हो सकता है, उसमें बदबू पैदा हो सकती है, इसलिए 7 जुलाई को नोटिस दिया, दोनों हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन को और उनसे निवेदन किया कि एम० पी० को आप सूचना कर दें कि अभी

7 जुलाई तक घी है, तो वे अपना कोटा अगले महीने का भी लेना चाहें तो ले लें, चुनाव के कुछ एम० पी० ने लिया भी लेकिन सब ले नहीं सके...

श्री लोकनाथ मिश्र (उड़ीसा) : आपका क्या यह इम्प्रेसन हुआ है कि हाउसिंग कमेटी का जो चेयरमैन है, वह डोमेस्टिक मेटर्स को देखता है?

प्रो० शेर सिंह : क्योंकि उनको मालूम है कि कौन कहां रहते हैं, सबके एड्रेस उनके पास है, एड्रेस भी बदलते रहते हैं और उनको सूचना दी। कई एम० पी० ने लाभ उठाया और घी लिया। तो एम० पी० में, मिनिस्टर्स में, सेक्रेटरीज में कोई भेदभाव इस मामले में है, यह बात नहीं। घी की कमी है इस देश में, यह बात ठीक है। इस साल दूध की विशेष कमी है। पिछले साल सूखा पड़ा और जब बहुत सारी चीजों की कीमत भी बढ़ी तो जैसे मोटा अनाज है, जो कि पशुओं के खाने में काम आता है उसकी कमी से भी कीमत बढ़ी। तो इस वजह से दूध भी कुछ कम पैदा हुआ और उसी के कारण घी भी कम बन रहा है और घी की कीमत बहुत ज्यादा है। दूध आने में दिक्कत दिल्ली में इसलिए हो रही है; क्योंकि घी की कीमत 20-25 रु० तक है एक किलो की। इसलिए जो दूध बेचा करता है वह समझता है घी बना लूं तो ज्यादा मुनाफा है। तो ये कठिनाइयां हैं और हमें यकीन है कोई न कोई समाधान हम निकाल लेंगे और जितना दूध हम देते हैं वह देते रहेंगे। यह ठीक है, थोड़ी फैट की मात्रा हम पूरी करेंगे धीरे-धीरे, क्योंकि फैट की अवेलेबिलिटी कम थी।

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, पहली बात तो मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना

चाहता हूँ कि जब आपने यह कहा कि नामल सप्लाई दूध की कम हो रही है और पिछले दिनों में दो बार आपने इस बात को दोहराया कि जो सप्लाई रही है उसमें कोई कमी नहीं आई या अनेक्केटेड रही टोटल क्वांटिटी दूध की, तो क्या आपको कभी यह मौका मिला है कि दिल्ली में दूध की बिक्री के समय, दूर नहीं तो यहां से मील-डेढ़ मील के आस-पास जो डिपो हैं, वहां का दृश्य देखने का किसी समय जाकर कष्ट किया, क्योंकि 4 बजे दोपहर के बाद जब डिपो ने खुलना होता है तो 3 बजे से तड़कती धूप में जिसमें 2 मिनट आदमी खड़ा होना मुश्किल महसूस करता है, वहां पर छोटे-छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाली लड़कियां और गृहणियां उस भीड़ के अंदर खिड़कियों पर लगी रहती हैं, कई-कई बार तो जैसे दम चढ़ रहा हो, यह हालत वहां दिखायी देती है। यह दृश्य यदि आप देख लें तो मैं समझता हूँ आपकी राय या आपका यह दावा कि दूध की कुल मात्रा में कमी नहीं आई, उस दावे को शायद आप बदल लें।

इसके साथ क्या आपको यह मालूम है कि नहीं कि इस समय जो लोग किसी कारण से दूध के बजार गुजारा नहीं कर सकते और घर में अगर कोई बीमार है या बच्चा है या कोई ऐसी स्थिति है, पहले चाय से चला लेते थे, अब नहीं चलाते हैं।

हम मेम्बरों के पास ऐसे लोगों के बराबर अनुरोध आते रहते हैं कि किसी तरह से सिफारिश करके, चिट्ठी लिख कर के या फिर मेडिकल आउन्डस पर ही दिला दिया जाय। इस तरह से यह जो दूध की कमी है, अगर इस कमी का ध्यान आप नहीं रखेंगे और केवल

यह दावा करते रहेंगे कि जो टोटल सप्लाई है उसमें कुछ कठिनाई आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि आप समस्या का हल ठीक तरह से नहीं कर पायेंगे और वह समस्या और भी कठिन हो जायेगी। इसलिए मैं आपका ध्यान इस चीज की तरफ दिलाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आप इस चीज के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं?

तीसरी चीज मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि 7 जुलाई को हमने सूचना दे दी थी। मैं नहीं जानता कि कितने माननीय सदस्यों को इस तरह की सूचना मिली, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझे इस बारे में सूचना नहीं मिली। शायद इसमें कुछ गलती हो गई हो, लेकिन हाउसिंग कमिटी के चेयरमैन उस काम के लिए उपयुक्त समझे जाय और उनके माध्यम से इस तरह की सूचना भेजी जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। वास्तव में मैं नहीं समझता कि उनके जिम्मे यह काम डालना कोई उचित बात थी। परन्तु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निकट भविष्य में घी के मिलने की कोई सम्भावना है? क्योंकि मिठाई बनाने के ऊपर बैन था और अब खोये में से भी प्रबन्ध हटा लिया गया है। दिल्ली में अब मिठाई बनाई जा रही है, बर्फी और दूसरी खोये की चीजों की मिठाई काफी तादाद में मिल रही है और बन रहीं हैं। लेकिन घी, जो कि मिठाई से भी ज्यादा जरूरी है, घरों में लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो बहुत जरूरी होता है, उसके मिलने की अभी कोई सम्भावना न हो, जो मिल्क डिपो हैं, जहां पर घी मिलता है, वे लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि घी कब से मिलने लगेगा, इसके बारे में मंत्री जी कुछ बतलायेंगे? आज बाजार में घी 22

[डा० भाई महावीर]

रुपया किलो बिक रहा है जो कि एक ज्विन्ता की बात है।

चौथी चीज में यह जानना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि हम बोतलों के ढक्कन बदलने की बात सोच रहे हैं और सबेरे स्टैंडर्ड मिल्क दें और शाम को टोन्ड मिल्क ही दें। क्या आप ने इस बात पर भी विचार किया है या कर रहे हैं कि जो इस समय बोतलों में दूध दिया जा रहा है, उनका रंग बदल दिया जाय। सिर्फ ढक्कन का रंग कुछ पहिचान के तौर पर रहे, तो उस ढक्कन को बदलने में थोड़ी सी होशियारी और तिगड़म की बात चाहिये और जो मुनाफा कमाने वाले लोग होते हैं, वे हर तरह की बात कर लेते हैं। इस काम में जो अनुस्कूपलस कर्मचारी होते हैं उनकी भी सहायता इसमें मिल जाती है। आज आप इस चीज को एक दम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में प्रयत्न किया जाय। जो बोतल का शीशा है उसका दो रंग हो। टोन्ड के लिए एक प्रकार का रंग इस्तेमाल किया जाय और दूसरे के लिए दूसरे प्रकार का रंग इस्तेमाल किया जाय। इसमें आसानी से शराबत करने की गुंजायश खत्म हो जायेगी।

आखिरी चीज में यह जानना चाहता हूँ कि आपने अभी जैसा कहा और हमने उसको मान लिया है कि हम हमेशा इम्पोर्टेड बटर आयल के भरोसे ही जीयेंगे? क्या हम इस मिल्क के सम्बन्ध में कोई और व्यवस्था नहीं करेंगे ताकि आठ साल, दस साल, बीस साल, सौ साल के बाद भी हम अपने दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुद समर्थ हो सकेंगे? इस बात की सम्भावना सरकार को दिखलाई देती

है या फिर इस बात के लिए कोई योजना सरकार के पास है? श्रीमन्, दिल्ली और राजस्थान के 800 मिल दूर स्थानों से हम दिल्ली में दूध लाते हैं। हमारी जो कुल आवश्यकता है उसको देख कर हमें यहां पर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हम स्वयं ही दूध का उत्पादन बढ़ा सकें और अपनी जरूरत स्वयं पूरा कर सकें। इस तरह की सरकार के पास कोई दीर्घकालीन योजना है या नहीं? अगर इस तरह की कोई योजना है तो वह क्या है?

प्रो० शेर सिंह: माननीय सदस्य ने चार प्रश्न उठाये हैं। पहिला प्रश्न इस बारे में था कि दूध के डिपोज में तीन बजे से पहिले ही भीड़ लग जाती है।

एक माननीय सदस्य: फिर भी लोगों को पूरा दूध नहीं मिल पाता है।

प्रो० शेर सिंह: पूरा दूध नहीं देते हैं, ऐसी बात नहीं है। असल में बात यह है कि बाजार में जो इस समय दूध का भाव है और जो दूध यहां पर मिलता है उसमें काफी अन्तर है। इसलिए लोगों की बड़ी कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से ज्यादा दूध प्राप्त कर लें और इधर उधर से ले लें। यह भी एक कारण भीड़ का है और भी कई कारण हो सकते हैं।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही ...

डा० भाई महावीर: कांड वालों को पूरा दूध नहीं मिलता है।

प्रो० शेर सिंह: इस बारे में भी शिकायतें आती रहती हैं और हम जांच भी करते रहते हैं। अगर आपके पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत है, तो कृपा करके आप हमें दे दीजिये और हम उसकी जांच करायेंगे।

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : आज से टोटल दूध मिलना शुरू हो गया है और 6 बोतलों के बजाय चार ही बोतल दूध मिला। इस बात को भी आप नोट कर लें।

प्रो० शेर सिंह : इस चीज के बारे में मैं मालूम करूंगा।

तीसरी बात आपने यह कही कि जो नये कोर्ड वाले हैं, बीमार आदमी हैं उनको दूध का कांड नहीं मिलता है और इस तरह के लोगों को दूध प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस समय दूध की कमिटेड सप्लाय है और जब तक हम इसका एक्सपेंशन और इसकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ायेंगे, तब तक हम दूध दूसरे लोगों को नहीं दे सकते हैं। हम दूध की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लान्ट के एक्सपेंशन का काम नवम्बर तक पूरा हो जायेगा और तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि नये कोर्ड वालों को दूध दे सकेंगे। हमारी कोशिश यह है कि हम 75 हजार लिटर दूध ज्यादा लोगों को दें और यह तब ही सम्भव होगा जब हमारा एक्सपेंशन का प्रोग्राम पूरा हो जायेगा। जिन आदमियों ने अपना नाम रजिस्टर करवा रखा है, जो नये कोर्ड बनाना चाहते हैं, इस नये प्रोग्राम के पूरा होने पर कर सकेंगे।

चौथी बात आपने रंग बदलने के सम्बन्ध में कही कि जो स्टैंडर्ड मिल्क है, टोटल मिल्क है, उनके बोतलों का रंग बदल दिया जाय। वह बात भी हमारे विचाराधीन है। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि सबेरे और शाम जो दूध दिया जाता है उनके बोतलों में भी कुछ लिख दिया जाय। किस तरीके से हम इस काम को अच्छी

तरह से कर सकते हैं, इस बारे में हम विचार कर रहे हैं और इन सब चीजों की जांच कर रहे हैं।

तो जो भी मथड ठीक होगा उसको करेंगे, लेकिन यह है कि यह बीमारी खत्म होनी चाहिए। आपने एक बात यह पूछी कि क्या कोई ऐसी दीर्घकालिक योजना है कि हम अपने देश में ज्यादा दूध पैदा कर सकें और विदेशों के ऊपर हमें निर्भर न रहना पड़े। पिछली जो पंच-वर्षीय योजनाएं चलती रहीं उनमें पहली तीन योजनाओं में कृषि पर बहुत कम बल था। चौथी योजना में कृषि पर जोर दिया गया, लेकिन एनिमल हसबैंड्री और दूध पैदा करने पर बहुत कम जोर दिया गया। ऐसी बात थी कि जो पैसा राज्य सरकारों को दिया जाता था वह एनीमल हसबैंड्री की जगह दूसरी चीजों पर खर्च होता रहा। चौथी योजना में 235 करोड़ खर्चा रखा गया था। लेकिन पांचवीं योजना में 700 करोड़ रखने का विचार है और हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इयरमार्क सेक्टर रखें ताकि जो पैसा इसके लिए दिया जाय वह इसी पर खर्च हो, दूध के उत्पादन को बढ़ाने, पशु पालन और पशुओं की नस्ल सुधारने तथा क्रॉस ब्रीडिंग पर ही खर्च हो।

डा० भाई भुवावीर : मैंने पूछा था कि खोए और दूसरी मिठाइयों पर से प्रतिबन्ध खुल जाने के बाद क्या घी बना कर लोगों को उपलब्ध करने की कोई योजना है? आपने आंकड़े दिए 700 करोड़ के। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि यह कल्पना है तो कब तक हम सेल्फ-सफिशिएन्ट होंगे?

प्रो० शेर सिंह : पांचवी योजना में मैंने निवेदन किया . . .

डा० भाई महावीर : पांचवीं योजना में हम आत्म-निर्भर हो जाएंगे।

प्रो० शेर सिंह : सैल्फ-सफिशिएन्ट तो मैं नहीं कह सकता। आज जो दूध हम अपने देश में पैदा करते हैं वह प्रति व्यक्ति 110 ग्राम के करीब मिलता है। पांचवी योजना 6 मिलियन टन बढ़ाने का विचार है। उसके बाद 140 ग्राम के करीब दे पायेंगे, लेकिन वास्तव में आवश्यकता ज्यादा है। जितना दूध लोगों को मिलना चाहिए उसके हिसाब से तो काफी समय लगेगा, लेकिन यत्न यही है कि पांचवी योजना में हम 6 मिलियन टन दूध बढ़ाएं और 700 करोड़ रुपया उसके लिए और सहायक प्रोग्रामों के लिए ही रखा है।

डा० भाई महावीर : घी का बताइए।

प्रो० शेर सिंह : जैसे दूध का आना बढ़ने लगेगा—आज से बढ़ना शुरू हुआ है—जैसे-जैसे दूध की मात्रा बढ़ेगी, घी बनाना शुरू कर देंगे। अभी कुछ दिन इन्तजार करना पड़ेगा।

SHRI LOKANATH MISRA : Sir, when you hear complaints almost from every Member of Parliament that the quota for which they have taken the permits was not available to them and they are persons who can ventilate their grievances amply on the floor of the House and put the Minister to a lot of difficulties, if they do not get the entire quota for which they hold permits, you can imagine the lot of the common man for whom this socialist Government is all the time crying, May I know when did the hon. Minister foresee that the weather was going to be bad this year and milk production was going to drop and would not be available to the extent it was available last year? What was the change in the weather, particularly this year, in order to bring down the production of milk? What are the ingredients of toned milk and standard milk? For the first time in my life I am hearing something called butter oil. Anything is now being adulterated with anything.

We were told that standard milk was buffalo milk. For Mr. Choudhury's information—he is an expert on cows and buffaloes—we are now told by the hon. Minister that standard milk is itself an adulterated thing. I think now toned milk is probably safer for consumption than standard milk. What is this* butter oil which is to be mixed in toned milk in order to make it standard milk? What are its ingredients? He imports it from abroad. Does he know what are its ingredients? Why do they mix it? Why do they mix it with toned milk in order to make it buffalo milk? Why is the direct and pure buffalo milk not being sold at whatever price it is available?

Therefore I would like to know what are the different ingredients in the different kinds of milk. Is milk powder a component also in this. And if milk powder and butter oil are mixed to make standard milk, then I would advise the Minister not to produce it hereafter and sell it as milk because people are under the impression that they are getting the purest milk when they get it from the DMS. Of course, now, with these caps being taken out and replaced, they have also started suspecting the quality of the milk supplied by the DMS. But would he kindly give us the different components and ingredients which are mixed in order to make the standard milk and the toned milk so that we will take care of ourselves rather than depending upon the Government?

PROF. SHER SINGH : The difference is between the standardised milk and the toned milk is that in the standardised milk the fat content is between 4.5 and 4.6 per cent . . .

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : We are talking of oil. Is it not vegetable oil?

PROF. SHER SINGH : That is butter oil.

SHRI LOKANATH MISRA : Are you sure that it is not beef fat?

SHRI SHER SINGH : It is butter fat. and this butter fat is imported from the ECM countries. We reconstitute the milk with the help of the skimmed milk powder

and butter oil. These are the ingredients. Now, we are combining these and then we reconstitute this milk which contains 4.5 per cent fat and 8.5 per cent SNF which is solid other than fat.

SHRI MAHAVIR TYAGI: Is it butter oil and not vegetable oil?

PROF. SHER SINGH: There is no adult ration in that. The toned milk contains 3 per cent fat. Of course the SNF is also 8.5 per cent. There is the double toned milk also. That contains 1.5 per cent fat. That is very cheap and it is supplied either to hospitals or small children through municipalities or in the jhuggi-jhompdi areas where there are poor people. That is subsidised.

SHRI LOKANATH MISRA: Do you have any milk without adulteration of the butter fat?

PROF. SHER SINGH: We receive some fresh milk, buffalo's milk as also some quantity of cow's milk. Cow's milk is supplied as raw's milk also direct. Standardised milk, toned milk and double-toned milk, these are the qualities that are supplied. I do not know if any other question was also asked.

SHRI LOKANATH MISRA: The other question was, how did you know that the weather was going to be bad this year and therefore the milk supply would dry up? Did you have any indication about it? You say that you forewarned also the MPs, which you did not do, and you said you wrote to the Chairmen of the House Committees as if they are the domestic managers.

PROF. SHER SINGH: That was about ghee because we knew that at that time on the 7th July, we were receiving a little fresh milk, about 40,000 litres only per day and therefore we could not manufacture ghee during that period: we were unable to manufacture. Then we informed the MPs to take their quota of August also because in August also it might be difficult for us to manufacture ghee. It was because of that that we gave that information.

11—9 RSS/ND/73

SHRI LOKANATH MISRA: Is there no butter oil content in the ghee that you supplied?

PROF. SHER SINGH: It is all pure ghee, 100 per cent.

SHRI KRISHAN KANT: May I know from the hon. Minister whether they have a regular system of checking that the caps in the bottles are not changed? Or do they take action only when newspaper reports come or an MP or somebody else refers the matter to them because every time we ask the question, the hon. Minister comes and says, if any case is referred to me, I will look into it. And the same thing is not solved. May I know, Sir, whether they have a regular system of inspection? Yesterday at the L'crozeshah Milk Depot I was told by the booth boys that the caps are changed in the milk van while we accuse these boys. He showed the caps. It means caps are changed during the carriage in the van. Even water is added during transit. May I know whether there is any way out against the private trader or those who sell adulterated milk? Can you not take action against them? What action do you take against people who carry milk in the Government milk vans? Will you take action against these government employees?

Further, when it is known to him that there is shortage of milk, may I know whether he discussed this matter with the Chief Minister of this State, Chaudhary Bansi Lai, who might have helped him in procurement of milk or does he propose to consult him now and invite him for discussion so that Haryana, which produces good milk, can also help in the supply of milk to Delhi? May I know whether the Government has any plan for a captive dairy for the Delhi Milk Supply so that we need not depend upon this supply of milk? He referred to the question of the Fifth Plan. May I know whether they have considered any plan of giving loans or help or grants to those unemployed people in the rural areas so that they could themselves start small dairies which can supply milk to the DMS? Whether, may I know, such a scheme was ever thought of or not?

[Shri Krishan Kant]

Lastly, we have been reading in the papers that lot of bogus cards from which milk is leaking out to the market are active. May I know whether they have taken any census of such cards, how much milk is leaking out to the market from the cards issued by the D.M.S. in the name of individuals?

PROF. SHER SINGH: In the statement itself in the beginning I said that the office of the D.M.S. regularly inspects the functioning of the milk depots in the city. It is not that we inspect only when we receive reports. Otherwise also there is regular inspection. There are 28 Inspectors and beats have been allotted to them. There are a number of depots allotted to each of the Inspectors. They inspect, these depots almost every week. This case of 21st August as also some other cases are cases where *sua molu* inspections were made and reports given about the removal of caps. Therefore, it is not that only on receiving complaints inspections are made on the depots. This is a regular practice.

His second point about Delhi getting milk from Hanuana, I discussed this matter with the Minister for Animal Husbandry, Haryana. We discussed about the supply of milk from Gurgaon and Rohtak areas through co-operative societies, and all the facilities that he wanted for the co-operative societies were extended. But somehow it could not be possible to start the supply. We are still in touch with the State Government of Haryana as also with the Government of Uttar Pradesh and Rajasthan. Even with Punjab we are negotiating to get more milk. As for having a small dairy for supplying milk to Delhi also, that is also receiving consideration.

Now, if we do not put up a dairy, then it may be possible that some animals may be given to farmers on loan as has been suggested by the hon'ble Member. Then milk could be procured from there. There is a scheme in the Fifth Plan for giving loans and also there is an element of sub-sidy for giving animals to small farmers, marginal farmers and agricultural labourers so that they can produce milk and supply it to the DMS.

SHRI KRISHAN KANT: I asked him as to how much milk is leaking to the market from the cards that are given. I also asked about the price rise.

PROF. SHER SINGH: I cannot exactly give the figure as to how much milk is leaking. It is very difficult to have that sort of an estimate. But we receive reports about it and we take action against those who are guilty of that. As for the price rise, we have to do it, because the farmer also cannot give the milk at the rates at which we had been getting it last year. Prices have gone up and if we increase the price of the milk that we purchase from the farmers, we may have to increase the price of the milk for the consumer also. Both these are under consideration in the Governing Body of the D.M.S.

श्री श्याम लाल गुप्त : मान्य महोदय, इसके पहले कि मैं अपनी बात कहना शुरू करूं, मैं आपको यह बता दूं कि आज पीने ग्यारह बजे यह दूध की बोतल यहां से खरीदी। मैंने यह पूछा कि यह दूध है या छाछ। तो कहा गया कि चख कर देख लो। मैंने चखा तो यह छाछ था। तो मैं मंत्री महोदय को यह पेश करता हूं कि वह चख कर देख लें या किसी को चखा कर देख लें कि क्या चीज है। यह अगर पालियामेंट हाउस के वृक्ष पर मिल सकता है तो आप अंदाजा कीजिये कि क्या हालत है। मैंने लिख कर दिया है लेकिन मैंने समझा कि आज आप तशरीफ ला रहे हैं तो इसको पेश करना अच्छा होगा। आज सबेरे ही अखबार में पढ़ा कि जब दो बोतल से अधिक एक कार्ड होल्डर को टॉड मिल्क नहीं मिलेगा। अगर यही हाल रहा तो एक फैमिली में जिसमें कि चार-पांच सदस्य हैं और उनका एक कार्ड है तो उनकी क्या हालत होगी।

दूसरे, जहां तक एडल्टेशन की बात है वह तो मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के बस से बाहर की चीज है।

जैसा कि हमारी बहन जी ने कहा चीजों में गाय और घोड़े की लीद मिलती है और काली मिर्च के अन्दर पपीते के बीज हैं। बहतेरी चीजें हैं। कम से कम जो यहाँ दूध देते हैं उसको तो ईमानदारी से दे दिया करें। मैं यह बोटल पेश करता हूँ।.... बोटल ले जावो।.... मैं बोटल पेश करता हूँ।

श्री उपसभापति: बोटल वगैरह बाहर दे दीजियेगा।

श्री श्याम लाल गुप्त: मैं बोटल पेश करता हूँ। यह है बोटल।

प्रो० शेर सिंह: दूध फट गया है।

श्री उपसभापति: श्री मान सिंह वर्मा।

श्री भान सिंह वर्मा: उपसभापति महोदय, दिल्ली दूध योजना के सम्बन्ध में यहाँ पर समय समय पर विचार होता रहा है और अभी इसी सप्ताह प्रश्न के रूप में इस पर विचार हुआ और माननीय मंत्री जी ने जहाँ तक मुझे याद है हमें चाही इस बात को स्वीकार किया है कि उसमें मिलावट भी होती है और उसकी डाट भी बदली जाती है और सब प्रकार की शरारतें वहाँ पर हो रही हैं और उनका कहना है कि जब जब हमें शिकायतें आती हैं हम उस पर एक्शन लेते हैं और कुछ लोगों को सजायें दी गई हैं उनके कथनानुसार। अब तक जो सजायें दी गई हैं समझता हूँ कि केवल बूथ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को सजायें दी गई हैं। मैं यह माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि मुझे शंका है, मुझे संदेह है, कि दिल्ली दुग्ध योजना में बड़ा भारी घोटाला है और उसमें केवल बूथ पर काम करने वाले छोटे कर्मचारी ही नहीं हैं बल्कि नीचे से ले कर ऊपर तक के सब मिले हुए

हैं। अभी भी इस प्रकार की शिकायतें आपकी नालेज में हैं। आप स्वीकार करते हैं हाउस के सामने, लेकिन उसका निराकरण हो नहीं पाता, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप कर नहीं पाते। कार्लिंग अटेंशन पर जो भी स्टेटमेंट आपने पढ़ कर दिया, मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी लिखा हुआ नीचे से आ गया आपने उसी प्रकार से पढ़ दिया। आपने जो स्वीकार किया है उसके अनुरूप आपका स्टेटमेंट नहीं है। तो आखीर को क्या आप कर रहे हैं इसको रोकने के वास्ते। मेरा यह चार्ज है कि पूरी स्कीम में घोटाला है और उसके लिए यह सुझाव है कि एक हार्ड पावर्ड कमेटी बना कर के इसका पूरा सर्वेक्षण कराना चाहिए, पूरा सर्वे होना चाहिये, निरीक्षण होना चाहिये। इसकी पूरी जांच करें। छोटे से ले कर बड़े तक इसमें शामिल हैं या नहीं। कहां पर एडल्ट्रेशन होता है, कहां पर क्या है।

एक दूसरी बात और है। मैंने आपसे मिल कर के एक सुझाव दिया था कि फार दि टाइम बीइंग आफ यह कर सकते हैं कि जहां आपके बूथ्स हैं उसके साथ जो भी क्षेत्र लगा हुआ है उस क्षेत्र के इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता या जिनके ऊपर आपको विश्वास हो कि यह ईमानदार और इंटेग्रिटी के लोग हैं उन दो-दो या तीन-तीन आदमियों का एक निरीक्षक-मंडल बना सकते हैं जो कि समय समय पर इस बात की देखरेख करते रहें, जांच करते रहें, कि वहां पर क्या होता है। आपने कहा कि नियमित रूप से निरीक्षण होता रहता है, यह भी कहना आपका गलत है। मैं बराबर कई साल से इसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। विट्ठलभाई पटेल भाई का जो बूथ है उसको स्वयं जाकर देखता हूँ। वैसे मुझे कोई पावर

[श्री मान सिंह बर्मा]

है नहीं मैं सारी बात को जांच कर लूँ मगर चूँकि वहाँ की रेजिडेंट कमेटी का कन्वीनर हूँ, उसके नाते से मैंने देखा है, उसका स्टडी किया है। तो मेरी प्रार्थना यह है कि आपका यह जो घोटाला है इसको आप केवल बूथ पर बैठे कर्मचारियों पर न डालिए, यह बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इसकी आपको स्वयं खोज करनी चाहिए उसकी जांच करनी चाहिए, उसके बाद आप समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

प्रो० शेर सिंह: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि क्या गड़बड़ होती है। मैंने उसको माना है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूँ कि गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं और जब उनकी रिपोर्ट आती है या जब अपने आप जाकर जांच करते हैं, जब उसमें कोई गलती निकलती है तो दण्ड भी देते हैं और केवल डिपो मैनेजर्स के लिए नहीं, ऊपर भी हम इस ढंग से बना रहे हैं कि हमने एक वाच सेल बनाया है जिससे यह देख सकें जो शिकायतें हमारे पास आती हैं और जो लोग इन्क्वायरी करके रिपोर्ट भेजते हैं उनसे कहें कि वे डेली अपनी रिपोर्ट भेजा करें कि कौन कौन से बूथ पर गए और जिस बूथ की शिकायत हमारे पास आई और उसने न भेजी हो तो समझ लेते हैं कोई गड़बड़ है और उसकी जांच होती है। तो इस तरह की भी व्यवस्था हम सोच रहे हैं।

श्री मान सिंह बर्मा: एक मिनट सुन लीजिए। चूँकि आप जांच के लिए कहते हैं, वे तो डेरी स्कीम के अधिकारी ही तो हैं, लेकिन अगर वही अधिकारी शामिल हैं और वे गड़बड़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास कौन चैनल है, कौन एजेंसी है?

प्रो० शेर सिंह: आपने जो सुझाव दिया है उस पर भी मैं आ रहा हूँ। आपने जो कहा है ठीक है। आपने जो अपना सुझाव दिया है कि कुछ पब्लिक के लोगों को भी इसके साथ एसो-शिएट करें, तो मेरा भी यह विचार है कि अगर बूथ-वाइज हम कोई ऐसा विलसिला कर सकें तो अच्छा हो। कठिनाई उसमें यह आती है कि अगर हमारे पांच-चार आदमी ऊपर से मनोनीत करें और क्योंकि इतना बड़ा शहर है, उसमें सब जगह जानना कि फलों बूथ पर कौन आदमी इतना अच्छा है और उसको चुनना, यह सरल काम नहीं है क्योंकि 1056 बूथ्स हैं। अगर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर हमने कोई आदमी चुन लिया, अच्छा आदमी, तो अगर दूसरी पार्टी आ जाए और कहे कि साहब एक पार्टी का आदमी रख दिया है कुछ इस तरह की कठिनाई भी इसमें है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि वहीं से बूथ-वाले अपनी मीटिंग करके अपने आदमी चुन कर दें कि हम पांच आदमी दे देते हैं जिसमें हम जगड़े पर न पड़ें, क्योंकि अगर हमने अपनी तरफ से अप्रॉइन्ट किए तो संजट हो सकता है। इसलिए अगर बूथ्स को पत्र लिख दें कि बूथ-वाइज पांच आदमियों की एकपंचायत समिति आप बना दीजिए, खुद अपनी मीटिंग करने दीजिए। और साथ ही उनको बदलना चाहिए, साल छः महीने में बदल सकते हैं, लेकिन ऐसी कमेटी बना के दें। हम कोशिश करेंगे, हम सब बूथ्स को लिखेंगे, और वे छानबीन कर लिया करें तो उससे ज्यादा मदद मिलेगी और उनकी कठिनाईयाँ सुन सकेंगे और हमारे पास भी रिपोर्ट कर सकेंगे। तो यह जो आपने सुझाव दिया वह ठीक है और हम सोच रहे हैं हम पत्र लिखें सबके पास, कुछ अखबारों में

निकालें, और उनसे कहें बूध-वाइज लोगों को एकट्ठा करके छोटी समितियाँ बना कर दे दें और उनकी जो रिपोर्टें आएँ उन पर फौरन एक्शन लिया करें। यह सुझाव आपका ठीक है।

श्री यशपाल कपूर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, यह दिल्ली दुग्ध संभरण योजना असल में बड़ी दुखदायी योजना शुरू से अब तक चली आई है जिससे जनता को दुःख . . .

डा० भाई महावीर : क्या आपका मतलब है दुग्ध संवर्द्धन की बजाएँ दुग्ध संवर्द्धन है ?

श्री यशपाल कपूर : मैंने कहा, दुःख दिया है। क्या राष्‍ट्र सभा में क्या लोक सभा में, दोनों जगहों में हर एक सत्र में यह बात उठायी जाती है किसी न किसी रूप में—कभी नीली टोपी लाल टोपी का झगड़ा हो जाता है कभी बोनल के अंदर कुछ निकल आता है और आज मंत्री महोदय ने बड़ी कुशलता से बताया कि बटर आइल से दूध बना कर दिया जाना है और बटर आयल और पाउडर को मिला कर, जैसा लोकनाथ मिश्र जी ने कहा, बड़ा शुद्ध दूध दिया जाना है। असल में बात यह है कि जब यह डी० एम० एस० शुरू की गई, तो बड़ी एक बुनियादी गलती यह की गई कि ऊपर का ढाँचा तो खड़ा कर दिया गया लेकिन जो दूध के स्रोत थे उनको निकालने का बढ़ाने की कोई योजना नहीं बनायी जब कि हमारे देश में ऐसे बहुत अच्छे और सफल उदाहरण मौजूद हैं। जैसा सबसे पहले आनन्द में शुरू हुआ, 500 गांवों को लेकर, जो भागे चल कर इतनी सफल योजना हो चली कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, मैसूर में भी उसकी नकल की गई और आज आनन्द

में दूध आपके अहमदाबाद और दूसरी तरफ—मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ—

एक माननीय सदस्य : मेहसाना।

श्री यशपाल कपूर : हाँ, मेहसाना, वहाँ से टैंकरों और रेल द्वारा दूध आप वहाँ लाते हैं। आपके ट्रक टैंकर दिल्ली से 150-200 मील की दूरी से दूध वहाँ पर लाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे दो प्रकार का शोषण हो रहा है। एक शोषण होता है दिल्ली की जनता का जो इतनी दूर से दूध लाने के बाद खर्चा देना पड़ता है उसकी वजह से कीमत बढ़ती है और इस कीमत को कंज्यूमर को भरना पड़ता है।

दूसरा शोषण होता है उन लोगों का जो आसपास के गांवों में रहते हैं। हम शहर वाले जो लोग हैं, चूँकि हम राजधानी में रहते हैं, इसमें साधारण जनता हो या पार्लियामेंट के मेम्बर हों, वे यह अपना प्रिविलेज जैसा समझते हैं कि हम चूँकि दिल्ली में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सब चीजें अच्छी मिलनी चाहिए। आप गांव के लोगों से उनका दूध छीन लेते हैं। मंत्री महोदय को यह मालूम होगा कि आपके कृषि विभाग ने एक अप्लाइड न्यूट्रेशन प्रोग्राम चलाया है, जो कि कई ब्लॉकों में चलाया जाता है।

एक माननीय सदस्य : वहाँ पर भी यह अप्लाई मुश्किल से ही होता है।

श्री यशपाल कपूर : वहाँ पर उनको प्रोटीन, दूध मिलता है जो गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं। एक तरफ तो आप इस एप्लाइड न्यूट्रेशन प्रोग्राम के लिए पैसा खर्च करते हैं और दूसरी ओर गांव में जो अच्छा दूध मिलता है उसको आप छीन कर के वहाँ पर ले आते

[श्री यशपाल कपूर]

हैं। आपने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं ताकि किसानों को सहायता मिल सके और इसके लिए बैंकों द्वारा और सरकार द्वारा धन की व्यवस्था किसानों के लिए की जाती है ताकि वे अपने लिए दुधारू जानवर खरीद सकें। आज इस तरह के दुधारू जानवरों की कीमत बढ़ गई है। आपके ही प्रदेश में ऐसे दुधारू जानवर मिलते हैं जो कि अच्छा दूध देते हैं। आप दिल्ली प्रदेश की हालत को देखें और दिल्ली में 20 मील बाहर जायें। सारे देश के लिए तो हमारा यह कार्यक्रम है कि गांवों की हालत अच्छी हो, किसानों की हालत अच्छी हो, जिनके पास जमीन नहीं है, उनकी हालत अच्छी हो। आप दिल्ली में बैठे हैं और उसके 300-350 गांवों की ऐसी हालत बना सकते हैं जिस पर हम फخر कर सकें और यह कह सकें कि हम गांव वालों की हालत बेहतर बना रहे हैं। हम बाकी देश के लिए, प्रदेशों के लिए एक नमूना दिखाने के गांवों में सुधार करके दिखाने। मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर जो कि कई बार उठाई जा चुकी है जरा गम्भीरता से विचार करें कि दिल्ली के 300-350 गांवों में और दिल्ली के सीमा पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के जो गांव आते हैं उनमें इस तरह का कार्य शुरू करें जिसमें हमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता मिल सके। सरकार को इन कामों में अपने साधनों को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहां पर अच्छे दुधारू जानवरों की संख्या बढ़ाइये। अगर आप दो साल के अन्दर इस तरह के कार्यक्रम से दुधारू जानवरों की संख्या बढ़ाते चले जायेंगे तो आज आपके दूध के डिपोज में जो भीड़ लगी रहती है वह

नहीं होगी और आप बाहर से बटर आयल और मिल्क पाउडर मंगाकर और दोनों को मिलाकर जो दूध यहां की जनता को देते हैं, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुःख की बात और कोई नहीं है। अगर आपको यहां की जनता का दुःख-दर्द दूर करना है, तो आप इस तरह की कोई कार्यवाही अवश्य करें।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता): दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिये।

प्रो० शेर सिंह: माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस समस्या का समाधान दूध का अधिक उत्पादन है। यह दिल्ली दुग्ध स्कीम जब बनाई गई थी, तब यह बात सोच ली गई थी कि यहां पर कृषि करने की जरूरत नहीं है। दूध तो चारों तरफ से मिल जायेगा और यहां पर दूध को इकट्ठा करके

प्रोसेस करने की बात थी। और अब

1 P.M. यह कठिनाई अनुभव हो रही है।

दूध की मात्रा बढ़ाने की तरफ अब ध्यान जा रहा है। आपरेशन फूलड का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें बाहर से बटर आयल और स्किमड पाउडर जो आता है उससे पैसा जेनरेट करके दूध को बढ़ाने का, मदर डेरी को बनाने का और जो अब 3 लाख लिटर देते हैं उसे बढ़ा कर पीने 8 लाख लिटर दूध देने की योजना है। दूध भी आमपास पैदा कर लें, ऐसा विचार है क्योंकि दिल्ली का देहात है, हरियाणा प्रदेश के गांव लगते हैं, उत्तर प्रदेश के गांव हैं जहां से दूध उपलब्ध हो सकता है। जैसा मैंने निवेदन किया, पांचवीं योजना में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है कि हम दूध का उत्पादन बढ़ाएं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जहां दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं वहां दूध का उत्पादन

बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय। यहां की अपनी नस्ल है, उस नस्ल को अच्छा बनाने, क्रॉस ब्रीडिंग करने और बाहर से एग्जाटिक कैटल लाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और ऐसा विचार भी है। इन उपायों को काम में लाकर दिल्ली के आसपास और देश के बाकी हिस्सों में दूध का उत्पादन बढ़ाया जाय वही समस्या का हल है।

माननीय सदस्य ने आनन्द का जो उदाहरण दिया उसी ढंग से करने का हमारा विचार है। जितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं वे इसी ढंग से होंगी कि कोऑपरेटिव्स के द्वारा दूध इकट्ठा करें जिससे फार्मर्स का शोषण न हो और ठीक मूल्य पर हम कन्ज्यूमर्स को अच्छा दूध दे सकें। इसी पैटर्न पर सारा आर्गेनाइज करना चाहते हैं।

DR. K. NAGAPPA ALVA (Mysore): Sir, this Calling Attention Notice: mainly concerns food adulteration. Milk is the main nutritional food. Large-scale adulteration of milk and milk product is going on in this country. The tragic situation at which we have arrived today is that we cannot find any of these food articles without adulteration. Now the responsibility of the Government has greatly increased, having taken over the wholesale food trade and I am happy the Government is in charge of the milk schemes and dairies and their Operations. It becomes all the more necessary that the Prevention of Food Adulteration Act should be enforced in all seriousness. I am happy that Shrimati Swati has brought forward this Calling Attention Notice and as she said there is no seriousness at all on the part of the Government. From top to bottom and from the bottom to the top there is infiltration and here I would only suggest that there is adulteration at different stages* from the milk from the cow upto the purchase and also at the preparation of the stuff. Sometimes, some of the Government officials are involved in these nefarious activities. Food adulteration amounts to crime, it amounts to spoiling the health of people and it amounts to murder. This con-

cerns not only the Food Ministry. Since the Calling Attention relates to Milk Scheme, the Agriculture Minister deals with it. Otherwise, it concerns the Agriculture Ministry, it concerns the Food Ministry, it concerns the Health Ministry and it also concerns the Home Ministry. It is because the concerned Act has to be faithfully implemented. So, Sir, I am asking what the arrangements are for supplying all these essential foodstuffs*, particularly milk and milk products, to all the people including the poorer sections of the society. It is unfortunate that we hear of these things being supplied mostly to the richer and privileged sections of society. Therefore, what is the action that they are going to take to have co-ordination and co-operation with all these departments to see that the foodstuffs are produced and also distributed and sold without adulteration and what would be the machinery that they would be setting up in the Agriculture Ministry to see that pure food is produced and distributed and what would be the machinery to put down the anti-social activities of the merchants and the officers. If they are involved in these things?

PROF. SH. R. SINGH: Sir, an impression has gone round that the milk and milk products supplied by the Delhi Milk Scheme are adulterated. It is not a fact. There is no adulteration in the milk products produced by the Delhi Milk Scheme, that is, ghee, ice cream or the other products that are produced. There is no adulteration in the milk supplied by the DMS. There is no adulteration at all. The very fact that we use skimmed milk powder and butter oil to reconstitute the milk does not amount to adulteration and it does not mean that we are adulterating it. So, there is no truth in saying that we do not take care of the health of the people and that adulteration is going on and the milk that we are supplying is below standard and is against the law, against the provisions of the Essential Commodities Act, etc., etc.

DR. K. NAGAPPA ALVA: But is the Government aware of the fact of adulteration at different stages?

PROF. SH. R. SINGH: In fact, in the case of all the milk products produced by the DMS- their specimens are taken and

[Prof. Sher Singh]

are analysed and are inspected regularly to find out whether they are up to the standard or not. We do not get laboratories . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : But he refers to a situation which arises after you despatch them.

PROF. SHER SINGH: Even after we despatch them and they go to the consumer, we do not have many complaints of adulteration. There may be cases of (hanging the caps or non-supply of 'lie quantity of milk to which a consumer is entitled and so on or one may not be getting in turn or somebody else is taking it away and so on. But there are no complaints of adulteration of the products produced by the DMS and we do not have any such complaints and if there are any complaints of that type and if the honourable Member brings them to our notice, we shall certainly get those things analysed, those products and I am not prepared to accept that there is adulteration in the products of the DMS. We are taking all care and the complaints that we receive are gone into in detail and we do not spare anybody howsoever high he may be and if he is found guilty, he is punished.

SHRI LOKANATH MISRA: Just a minute. Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just wait. Mr. Sinha wants to say something.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA (Bihar): Sir, I would put a very specific question to my friend and if he has no answer to that at present, he must give me the reply later.

Sir, every year the shopkeepers are ordered not to prepare the milk products and sweets like sandesh, rasagulla, khoya, etc. during a particular period, during a few months, because of the scarcity of milk. This year the monsoon has come late and I think there is a committee which decides which products should be allowed and which should not be allowed. Sir, I come from an area where the people including me cannot do without rasagullas and sandesh. Even at this age, at two o'clock at night if you wake me up and give me this, I will not hesitate to take it and I will not refuse it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are lucky because you are not a diabetic. I hope.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Yes, I am not a diabetic. Sir, some people make these things, the rasagullas and other things and I refuse to take them because there is a ban on them. I bring it from Patna and other places or from Calcutta, from my friends. But I did not take 'rasagulla' prepared here, out of the deference to their decision.

Now, Sir, scarcity is the cause of many ills. This Committee this year has not taken the decision with a sense of responsibility, because they knew that there was scarcity of milk. My charge is that they had been pressurized by the shopkeepers. That is my charge, whosoever be in the Committee. Who are the members of the Committee? Why did they decide this year like this? This gentleman, the Chairman of the Delhi Milk Scheme, is sitting here. He promised that they will give *ghee* to Members of Parliament by the 15th of August. Then we got the information that they will give it after Janmashtami. And now it is whispered that we will be getting by the 25th of September. What is the answer to this question?

PROF. SHER SINGH: Sir, every year, as the hon. Member has said, we ban the manufacture of *khoya* and other such products from the month of May. This ban goes up to 15th of July mostly. Last year, it went up to the 7th July because we had very good rains. This year we extended it up to the 31st July. But I think it was only after we had very good rains in all the areas round about Delhi that the ban was lifted, and this was 10-12 days later than the time-limit that is ordinarily fixed, i.e., the 15th of July. I do not remember the exact date. It may be 25th or 26th.

Now, as far as the manufacture of *ghee* is concerned, as I already submitted, Sir . . .

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: In view of the result that has been obtained now, do you think that the decision of the Committee was proper?

PROF. SHER SINGH: Because of drought conditions and because a long spell of heat, we had to extend it. We extended it...

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA : They should have further extended it . . .

PROF. SHER SINGH: The Delhi Administration have been approaching us from the very beginning not to extend it beyond the 7th July. We said, 'no'. Even after the 15th July, they again approached us. But it was only after we had good rains that we lifted the ban, otherwise that continued beyond 15th July, which is the normal date for lifting the ban.

SHRI LOKANATH MISRA: Sir, since von and we all sit under 'Satyameva Jayate', in order to protect Truth, they may re-name the Delhi Milk Scheme as 'Delhi Artificial Milk Scheme'.

ANNOUNCEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE FOR PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): With your permission Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 27th August, 1973, will consist of:

(1) Consideration of a Resolution regarding Orissa Electricity Board.

(2) Consideration and passing of the Cinematograph (Second Amendment) Bill, 1973.

(3) Consideration and return of the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1973, as passed by Lok Sabha.

(4) Discussion on the 22nd Report of the Union Public Service Commission.

(5) Discussion under Rule 176 on the Report of Shri Justice Rajinder Sachar on the accident to the Indian Airlines Boeing near Palam on May 31, 1973.

(6) Consideration and passing of:

(i) The Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 1975.

(ii) The Foreign Exchange Regulation Bill, 1973, as passed by Lok Sabha.

Sir, to complete this Government business, and other important as allowed by the Chairman, the House will sit on 2nd and 4th September.

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 24th August, 1973, allotted time as follows for Government Legislative and other Business to be taken up during the remaining part of the current Session of the Rajya Sabha:

Business	Time Allotted
1. Statutory Resolution relating to the Orissa State Electricity Board.	1 hour
2. Consideration and passing of the Cinematograph (Second Amendment) Bill, 1973.	3 hours
3. Consideration and return of the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1973, as passed by the Lok Sabha.	2 hours 30 minutes
4. Consideration and passing of:	
(i) The Industries (Development and Regulation) Amendment Bill 1973.	2 hours
(ii) The Foreign Exchange Regulation Bill, 1973, as passed by the Lok Sabha.	4 hours
(iii) The Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 1973, as passed by the Lok Sabha.	1 hour
(iv) The Direct Taxes (Amendment) Bill, 1973, as passed by the Lok Sabha.	3 hours

7-9 RSS/ND/73